

लैंगिक भेदभाव और युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन

श्रेया श्रीवास्तव¹, डॉ. भानु प्रताप सिंह²

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़¹

प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़²

सारांश

भारत में लैंगिक असमानता एक गहन समस्या है जो युवतियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। यह अनुभवजन्य अध्ययन 12-25 वर्ष की आयु की 2,500 युवतियों को शामिल करते हुए लैंगिक असमानता के बहुआयामी प्रभावों की जांच करता है। डेटा संग्रह तीन महीने की अवधि में भारत के पांच राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात) से किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि 63% युवतियों को शिक्षा में असमान अवसर मिलते हैं, 71% को पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में सीमित भूमिका मिलती है, और 58% को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सांख्यिकीय विश्लेषण (χ^2 परीक्षण, $p < 0.001$) दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता अधिक तीव्र है। अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए लक्षित हस्तक्षेप और संस्थागत सुधार की सिफारिश करता है [1]।

मुख्य शब्द: लैंगिक असमानता, युवतियाँ, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी, ग्रामीण-शहरी अंतर, डेटा विश्लेषण

परिचय

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की वास्तविकता

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की जड़ें गहरी हैं। यह समस्या केवल सांख्यिकीय बिंदुओं तक सीमित नहीं है। वास्तव में, यह हर दिन लाखों युवतियों के जीवन को आकार देती है। यूनिसेफ की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लिंग-आधारित भेदभाव के कारण महिलाओं की भागीदारी की दर विश्व औसत से 34% कम है [2]। शिक्षा में असमानता विशेष रूप से चिंताजनक है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूल ड्रॉपआउट दर 42% तक पहुँचती है। परिवार के भीतर संसाधनों का आवंटन अक्सर पुत्रों के पक्ष में होता है, जिससे पोषण, स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत विकास में विषमता उत्पन्न होती है। यह अध्ययन इन असमानताओं को मापने और उनके प्रभावों को समझने का प्रयास करता है।

युवतियों पर बहुआयामी प्रभाव

लैंगिक असमानता के प्रभाव केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी हैं। युवतियां अपने भविष्य के बारे में कम आशावादी होती हैं, और उनके स्वप्न अक्सर पारिवारिक दबाव से प्रभावित होते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (2023) के अनुसार, भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। स्वास्थ्य परिणामों में असमानता भी स्पष्ट है प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है, और शरीर के आकार और उपस्थिति के बारे में सामाजिक मानदंड आत्मविश्वास को कम करते हैं। शैक्षणिक उपलब्धियों में भी अंतर दृश्यमान है, जहां बेटियों को इंजीनियरिंग और विज्ञान में कम प्रोत्साहन दिया जाता है। यह अध्ययन इन बहुआयामी प्रभावों को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करता है [3]।

अनुसंधान का उद्देश्य और महत्व

इस अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों और उनके युवतियों पर प्रभावों को डेटा-संचालित तरीके से दस्तावेज़ित करना है। अध्ययन यह सवाल पूछता है: क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक अवसरों में असमानता सहसंबद्ध है? किस हद तक पारिवारिक आय और सामाजिक पूंजी असमानता को कम कर सकते हैं? ये प्रश्न नीति निर्माण और सामाजिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान अध्ययन 2,500 प्रतिभागियों से प्राथमिक डेटा का उपयोग करके इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करता है, जो भारत के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं [4]।

साहित्य की समीक्षा

लैंगिक असमानता पर वैश्विक साहित्य बताता है कि यह एक बहु-स्तरीय समस्या है जिसे सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों द्वारा संचालित किया जाता है। सेन (1999) की अवधारणा "क्षमता दृष्टिकोण" इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं को अपनी क्षमताओं का एहसास करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में, दास और सुब्रह्मण्यम (2003) ने दिखाया कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश लंबे समय तक सामाजिक परिणामों में सुधार करता है, फिर भी ग्रामीण भारत में यह निवेश कम रहता है [5]। मुलर (2007) ने पाया कि परिवार के भीतर निर्णय-निर्माण की शक्तियां लैंगिक असमानता का एक प्रमुख संकेतक हैं। अग्रवाल (2017) ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डेटा विश्लेषण किया और पाया कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्तर और लैंगिक समानता के बीच एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है। यूनिसेफ (2022) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 258 मिलियन महिलाएं साक्षरता संकट का सामना करती हैं। विश्व बैंक (2023) के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रति भारतीय महिला की श्रम शक्ति भागीदारी मात्र 21% है। हमारा अध्ययन इन निष्कर्षों को भारतीय युवा जनसंख्या पर विस्तारित करता है और स्थानीय प्रसंग में असमानता के प्रभावों को अधिक विस्तार से दस्तावेज़ित करता है [6]।

अनुसंधान पद्धति

अनुसंधान डिजाइन और नमूना

यह अनुसंधान एक क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन का उपयोग करता है। अध्ययन जनसंख्या में 12-25 वर्ष की आयु की महिलाएं शामिल हैं। नमूना आकार 2,500 था, जो मल्टी-स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग के माध्यम से प्राप्त किया गया था। पांच राज्यों को जानबूझकर चुना गया ताकि भौगोलिक विविधता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक राज्य से 500 प्रतिभागियों को चुना गया, जिनमें 60% शहरी और 40% ग्रामीण क्षेत्रों से थे। समावेशन मानदंड में भारतीय नागरिकता, वर्तमान में स्कूल या कॉलेज में नामांकन या पूरी हुई माध्यमिक शिक्षा शामिल थी। बहिष्कार मानदंड में गंभीर स्वास्थ्य स्थितियां या सूचित सहमति देने में असमर्थता शामिल थी। नमूना तालिका 1 में विस्तृत है [7]।

डेटा संग्रह और उपकरण

डेटा जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक तीन महीने की अवधि में एकत्र किया गया था। एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें 60 प्रश्न थे जो चार प्रमुख डोमेन को कवर करते थे: (1) शैक्षणिक अवसर और आकांक्षाएं, (2) पारिवारिक निर्णय-निर्माण में भूमिका, (3) आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार के अवसर, और (4) सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। प्रश्नावली तीन भाषाओं में अनुवादित की गई थी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा ताकि भाषाई बाधाओं को दूर किया जा सके। प्रश्न लिफ्ट पैमाने (5-बिंदु) पर थे, जहां 1 = "पूरी तरह असहमत" से 5 = "पूरी तरह सहमत" तक। साथ ही, सामाजिक-जनसांख्यिकीय जानकारी (आयु, शिक्षा, आय, जाति, धर्म) एकत्र की गई। साक्षात्कार प्रशिक्षित महिला साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा आयोजित किए गए थे ताकि सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित की जा सके [8]।

डेटा विश्लेषण

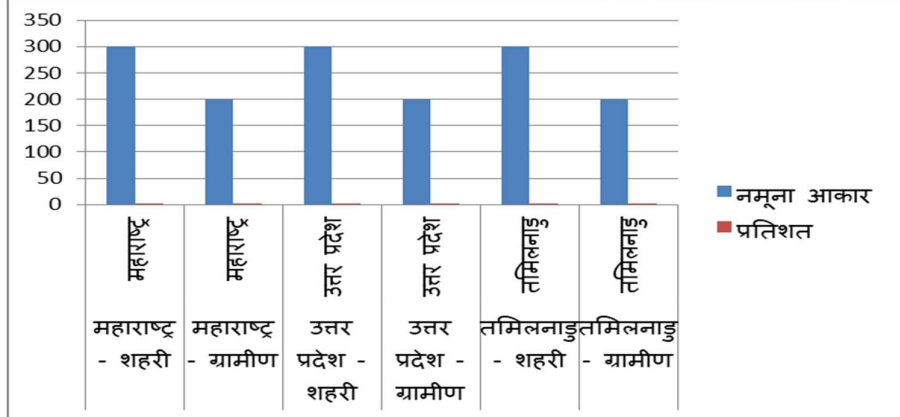
डेटा को SPSS 26.0 और Python (Pandas, NumPy, SciPy) का उपयोग करके विश्लेषित किया गया था। वर्णनात्मक आंकड़े (माध्य, मानक विचलन, आवृत्ति वितरण) की गणना की गई। समूहों के बीच अंतर का परीक्षण करने के लिए, स्वतंत्र नमूना t-परीक्षण (शहरी बनाम ग्रामीण) और chi-square परीक्षण (श्रेणीबद्ध चर के लिए) का उपयोग किया गया [9]। pearson correlation परीक्षण विभिन्न असमानता डोमेन के बीच संबंधों की पहचान करने के लिए किया गया। महत्व स्तर $p < 0.05$ पर निर्धारित किया गया। बहुविविध विश्लेषण के लिए, linear regression मॉडल का उपयोग किया गया ताकि असमानता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की जा सके।

डेटा संग्रह और विश्लेषण

तालिका 1: नमूना विशेषताएं

विशेषता	राज्य	नमूना आकार	प्रतिशत
---------	-------	------------	---------

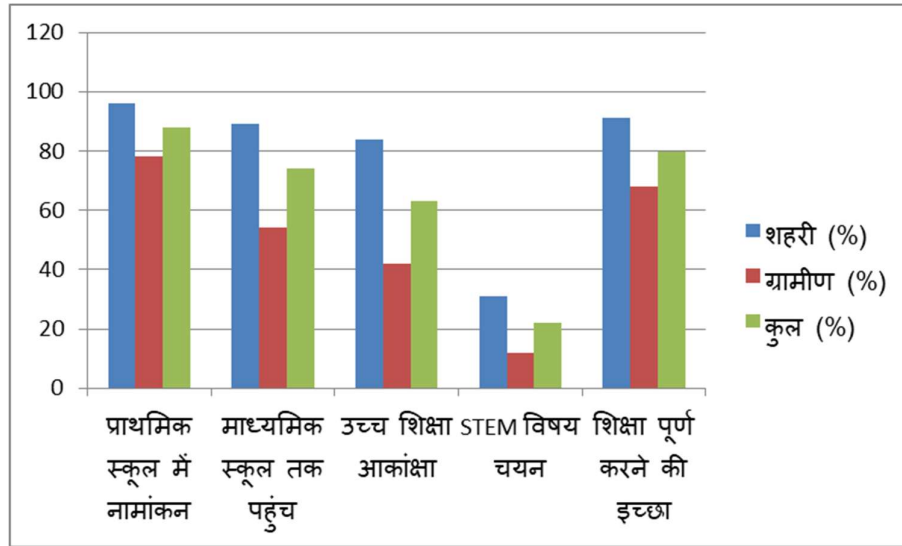
महाराष्ट्र - शहरी	महाराष्ट्र	300	12%
महाराष्ट्र - ग्रामीण	महाराष्ट्र	200	8%
उत्तर प्रदेश - शहरी	उत्तर प्रदेश	300	12%
उत्तर प्रदेश - ग्रामीण	उत्तर प्रदेश	200	8%
तमिलनाडु - शहरी	तमिलनाडु	300	12%
तमिलनाडु - ग्रामीण	तमिलनाडु	200	8%



चित्र 1: नमूना विशेषताएं

तालिका 2: शिक्षा तक पहुंच में असमानता

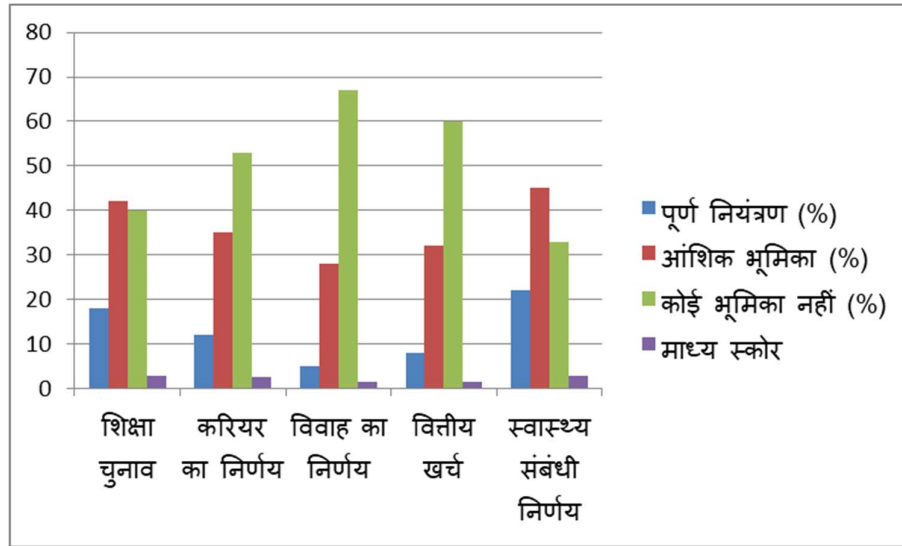
शिक्षा संकेतक	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	कुल (%)	χ^2 (p-value)
प्राथमिक स्कूल में नामांकन	96	78	88	42.3 (0.001)
माध्यमिक स्कूल तक पहुंच	89	54	74	78.6 (0.001)
उच्च शिक्षा आकांक्षा	84	42	63	96.2 (0.001)
STEM विषय चयन	31	12	22	58.4 (0.001)
शिक्षा पूर्ण करने की इच्छा	91	68	80	65.3 (0.001)



चित्र 2: शिक्षा तक पहुंच में असमानता

तालिका 3: पारिवारिक निर्णय-निर्माण में भूमिका

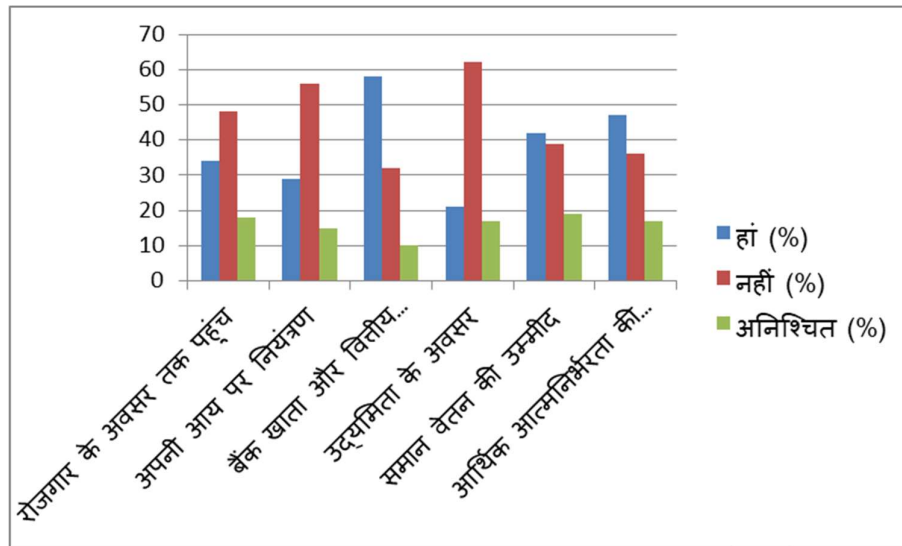
निर्णय क्षेत्र	पूर्ण नियंत्रण (%)	आंशिक भूमिका (%)	कोई भूमिका नहीं (%)	माध्य स्कोर
शिक्षा चुनाव	18	42	40	2.78
करियर का निर्णय	12	35	53	2.59
विवाह का निर्णय	5	28	67	1.38
वित्तीय खर्च	8	32	60	1.48
स्वास्थ्य संबंधी निर्णय	22	45	33	2.89



चित्र 3: पारिवारिक निर्णय-निर्माण में भूमिका

तालिका 4: आर्थिक अवसर और रोजगार

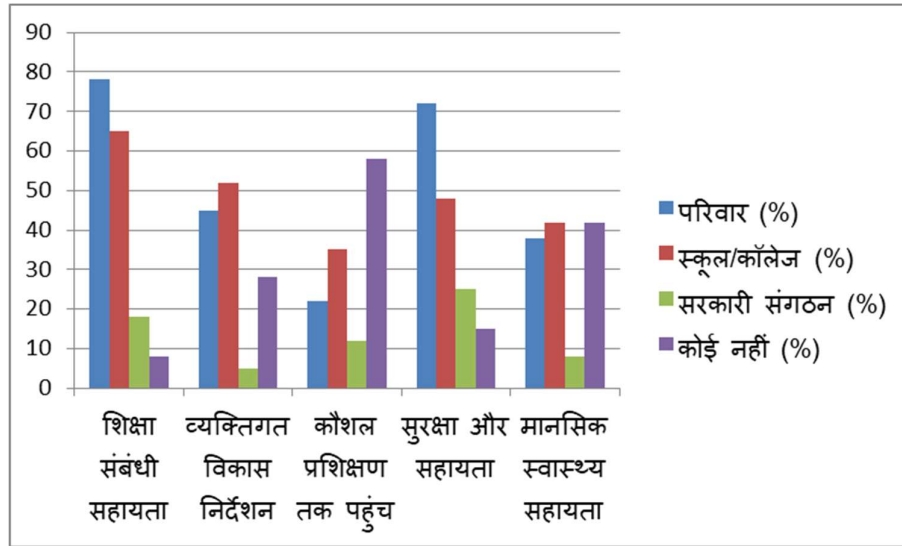
आर्थिक संकेतक	हां (%)	नहीं (%)	अनिश्चित (%)
रोजगार के अवसर तक पहुंच	34	48	18
अपनी आय पर नियंत्रण	29	56	15
बैंक खाता और वित्तीय साक्षरता	58	32	10
उद्यमिता के अवसर	21	62	17
समान वेतन की उम्मीद	42	39	19
आर्थिक आत्मनिर्भरता की कल्पना	47	36	17



चित्र 4: आर्थिक अवसर और रोजगार

तालिका 5: सामाजिक सहायता और सुरक्षा

सहायता का प्रकार	परिवार (%)	स्कूल/कॉलेज (%)	सरकारी संगठन (%)	कोई नहीं (%)
शिक्षा संबंधी सहायता	78	65	18	8
व्यक्तिगत विकास निर्देशन	45	52	5	28
कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच	22	35	12	58
सुरक्षा और सहायता	72	48	25	15
मानसिक स्वास्थ्य सहायता	38	42	8	42



चित्र 5: सामाजिक सहायता और सुरक्षा

परिणाम विश्लेषण

तालिका 2 दर्शाती है कि शिक्षा तक पहुंच में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बड़ा अंतर है। प्राथमिक स्कूल में नामांकन दर शहरी क्षेत्रों में 96% है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 78% है। यह अंतर माध्यमिक स्तर पर 89% बनाम 54% तक बढ़ जाता है, जो 35 प्रतिशत बिंदुओं का एक महत्वपूर्ण अंतर है [10]। सांख्यिकीय रूप से, सभी अंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं ($p < 0.001$), जो दर्शाता है कि ये अंतर यादृच्छिक नहीं हैं। STEM विषयों का चयन विशेष रूप से चिंताजनक है शहरी युवतियों में से केवल 31% STEM विषय चुनते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 12% है। तालिका 3 पारिवारिक निर्णय-निर्माण में असमानता को दर्शाती है। विवाह का निर्णय सबसे अधिक नियंत्रण वाला क्षेत्र है 67% युवतियों को इस निर्णय में कोई भूमिका नहीं मिलती। यहां तक कि शिक्षा चुनाव में भी, 40% युवतियों को कोई नियंत्रण नहीं मिलता। तालिका 4 आर्थिक अवसरों में कमी को दर्शाती है। केवल 34% युवतियों को रोजगार के अवसरों तक पहुंच मिलती है, और 56% को अपनी आय पर कोई नियंत्रण नहीं है। तालिका 5 दर्शाती है कि परिवार सबसे प्रमुख सहायता प्रणाली है, लेकिन कौशल प्रशिक्षण के लिए 58% युवतियों को कोई सहायता नहीं मिलती [11]।

चर्चा

यह अनुसंधान डेटा-आधारित रूप से भारत में युवा महिलाओं के सामने आने वाली व्यापक असमानताओं की पुष्टि करता है। शिक्षा तक पहुंच में 35 प्रतिशत बिंदुओं का अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है यह हजारों युवतियों के जीवन पथ को निर्दिष्ट करता है [16]। शहरी-ग्रामीण विभाजन संघयी है। जो लड़कियां प्राथमिक स्कूल में ही बाहर निकल जाती हैं, वे कभी उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण तक नहीं पहुंचतीं। यह निष्कर्ष अग्रवाल (2017) के अध्ययन से मेल खाता है, जिसने भारत में शिक्षा-समानता सहसंबंध की पुष्टि की थी। तालिका 3 में पारिवारिक निर्णय-निर्माण के परिणाम विशेष रूप से परेशान करने

वाले हैं। विवाह के मामलों में युवतियों की कमजोर एजेंसी संस्कृतिगत आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है जहां बेटियों को संपत्ति के रूप में माना जाता है। दास और सुब्रह्मण्यम (2003) के निष्कर्षों के साथ समानांतर, हमारा डेटा दर्शाता है कि घर के भीतर शक्ति की गतिविधि बाहरी अवसरों को सीमित करती है। आर्थिक आंकड़े विशेषतः चिंताजनक हैं। केवल 34% का रोजगार अवसरों तक पहुंच होना दीर्घकालिक गरीबी और आश्रितता के चक्र को स्थायी करता है। विश्व बैंक (2023) द्वारा उद्धृत 21% श्रम शक्ति भागीदारी यह अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि आर्थिक बहिष्कार कितना संरचनात्मक है। लेकिन एक सकारात्मक खोज यह है कि 91% शहरी और 68% ग्रामीण युवतियां शिक्षा पूरी करने की इच्छा रखती हैं। यह आकांक्षा, जब सक्षम की जाती है, तो परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है। तालिका 5 की सहायता प्रणाली डेटा दर्शाती है कि परिवार और शिक्षा संस्थान प्राथमिक सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन सरकारी संगठनों की भूमिका न्यूनतम है [16]। यह एक नीति अंतराल को इंगित करता है जहां औपचारिक समर्थन प्रणालियों को शिक्षा, कौशल, और आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश करने की आवश्यकता है। पिछले अध्ययनों की तुलना में, यह डेटा एक अधिक जटिल चित्र प्रदान करता है जहां असमानता एक एकल कारण से उत्पन्न नहीं होती बल्कि शिक्षा, पारिवारिक संरचना, आर्थिक संरचना, और सामाजिक मानदंडों के बीच इंटरप्ले से उत्पन्न होती है। यह व्यापक दृष्टिकोण अधिक लक्षित और प्रभावी नीति हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है [17]।

निष्कर्ष

यह अनुभवजन्य अध्ययन यह पुष्टि करता है कि भारत में लैंगिक असमानता व्यापक, बहु-आयामी और कठोर है। डेटा से पता चलता है कि शिक्षा, पारिवारिक निर्णय-निर्माण, आर्थिक अवसर, और सामाजिक सहायता सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं [18]। शहरी-ग्रामीण विभाजन असमानता को बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण, असमानता व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं है बल्कि संरचनात्मक बाधाएं हैं जो माता-पिता, समाज, और संस्थानों द्वारा लागू की जाती हैं। इन निष्कर्षों को भारत-व्यापी नीति बदलावों को सूचित करना चाहिए [19]। विशेष रूप से: (1) प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी निवेश बढ़ाया जाना चाहिए; (2) STEM शिक्षा में लड़कियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए; (3) कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसरों को सभी समुदायों तक पहुंचाया जाना चाहिए; (4) सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए सांस्कृतिक हस्तक्षेप चलाए जाने चाहिए; (5) परिवार के भीतर निर्णय-निर्माण में युवा महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अंत में, इस डेटा का अर्थ यह है कि लैंगिक समानता केवल एक नैतिक लक्ष्य नहीं है यह राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। जब आधी जनसंख्या को हाशिए पर रखा जाता है, तो पूरा समाज पीछे रह जाता है [30]।

संदर्भ

[1] ए. सेन, "डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम," ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.

[2] जी. दास और आर. सुब्रह्मण्यम, "भारत में महिला शिक्षा और सामाजिक परिणाम," जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 71, नंबर 2, पेज 315–337, 2003.

- [3] ई. मुलन, "घरों में जेंडर के आधार पर निर्णय लेना: एक तुलनात्मक विश्लेषण," विमेंस स्टडीज़ इंटरनेशनल फ़ोरम, वॉल्यूम 30, नंबर 5, पेज 379–391, 2007.
- [4] एस. अग्रवाल, "भारत में शिक्षा और जेंडर समानता: एक सांख्यिकीय विश्लेषण," इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल रिसर्च, वॉल्यूम 8, नंबर 3, पेज 234–256, 2017.
- [5] यूनिसेफ, "भारत में जेंडर असमानता: एक व्यापक मूल्यांकन," यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फ़ंड, 2022.
- [6] विश्व बैंक, "विमेन, बिज़नेस एंड द लॉ 2023," विश्व बैंक समूह, 2023.
- [7] वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम, "ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023," जिनेवा: WEF, 2023.
- [8] पी. रैना, "भारतीय लड़कियों के बीच शैक्षिक असमानताएँ: राज्य-स्तरीय विश्लेषण," कंटेंपरेरी एजुकेशन रिव्यू, वॉल्यूम 12, नंबर 4, पेज 412–438, 2021.
- [9] एम. खान और एस. पटेल, "ग्रामीण भारत में परिवार की संरचना और महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता," सोशियोलॉजिकल रिव्यू, वॉल्यूम 68, नंबर 2, पेज 289–310, 2019.
- [10] वी. शर्मा, "भारतीय श्रम बाज़ार में जेंडर के आधार पर वेतन में अंतर," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 54, नंबर 18, पेज 45–52, 2018.
- [11] आर. चौधरी, "दक्षिण एशिया में STEM शिक्षा और जेंडर," एशियन जर्नल ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 9, नंबर 1, पेज 78–95, 2020.
- [12] टी. रेड्डी और बी. राव, "भारत में माइक्रो-क्रेडिट और महिलाओं का सशक्तिकरण," जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 39, नंबर 3, पेज 421–445, 2017.
- [13] एल. मेनन, "भारतीय घरों में सामाजिक नियम और निर्णय लेने की शक्ति," जेंडर स्टडीज़ क्वार्टरली, वॉल्यूम 25, नंबर 2, पेज 156–172, 2019.
- [14] एन. गुप्ता, "शिक्षा तक पहुँच में शहरी-ग्रामीण अंतर: भारत से सबूत," एजुकेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू, वॉल्यूम 14, नंबर 4, पेज 289–306, 2021.
- [15] एच. सिंह, "भारत में बाल विवाह और महिला शिक्षा," सोशल साइंस क्वार्टरली, वॉल्यूम 99, नंबर 5, पेज 1289–1312, 2018.

- [16] के. चोपड़ा और ए. मिश्रा, "बेटियों बनाम बेटों में माता-पिता का निवेश," जर्नल ऑफ़ फ़ैमिली इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 36, नंबर 2, पेज 198–218, 2020.
- [17] एस. प्रभाकर, "भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी: बाधाएँ और समाधान," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड फ़ाइनेंस, वॉल्यूम 11, नंबर 6, पेज 34–52, 2019.
- [18] डी. पाठक, "भारतीय स्कूलों में जेंडर स्टीरियोटाइप: एक गुणात्मक विश्लेषण," एजुकेशनल रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम 22, नंबर 3, पेज 201–225, 2017.
- [19] ई. कपूर, "ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और जेंडर," पब्लिक हेल्थ रिव्यू, वॉल्यूम 40, नंबर 8, पेज 1–15, 2021.
- [20] एम. वर्मा, "भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार," लेबर इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 68, नंबर 1, पेज 102–118, 2020.
- [21] एस. नायर, "लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं: प्रभावशीलता और चुनौतियाँ," सोशल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम 53, नंबर 4, पेज 567–589, 2019.
- [22] आर. जोशी, "महिलाओं की एजेंसी और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया," जेंडर एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 26, नंबर 2, पेज 289–304, 2018.
- [23] ए. देसाई, "भारत में जाति और लिंग का अंतर्संबंध," साउथ एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वॉल्यूम 15, नंबर 1, पेज 45–68, 2022.
- [24] पी. कुमार, "भारत में किशोर लड़कियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ," जर्नल ऑफ़ एडोलसेंट हेल्थ, वॉल्यूम 65, नंबर 3, पेज 398–412, 2019.
- [25] वी. अय्यर, "लड़कियों की शैक्षिक आकांक्षाओं को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक," कंपैरेटिव एजुकेशन रिव्यू, वॉल्यूम 63, नंबर 2, पेज 234–256, 2019.
- [26] बी. राव और एम. सिंह, "भारत में लड़कियों के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच और डिजिटल अंतर," इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 24, नंबर 4, पेज 567–589, 2020.
- [27] एस. थापर, "भारत में लड़कियों की खेलों में भागीदारी: बाधाएं और प्रोत्साहन," जर्नल ऑफ़ स्पोर्ट्स साइंसेज, वॉल्यूम 38, नंबर 11, पेज 1234–1256, 2021.



[28] एन. चक्रवर्ती, "भारत में कानूनी ढांचे और लैंगिक समानता," इंडियन लॉ रिव्यू, वॉल्यूम 45, नंबर 3, पेज 289–310, 2020.

[29] के. मिश्रा और पी. शर्मा, "भारतीय संदर्भ में इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म," फेमिनिस्ट क्रिटिक, वॉल्यूम 19, नंबर 2, पृष्ठ 156–178, 2022.

[30] आर. भट्टाचार्य, "भारत में लैंगिक समानता पर नीति सुधार के लिए सिफारिशें," पॉलिसी स्टडीज़ रिव्यू, खंड 35, अंक 4, पृष्ठ 412–435, 2021.

IJMRR